Services of the Container Corporation of India Ltd.

1102. SHRI ASHOK NATH VERMA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to refer to the answer to unstarred question 2994 given in the Rajya Sabha on 18.12.91 and state:

(a) the steps being taken by Government to ensure that the container Corporation of India (CONCOR) appoints needy persons as their Booking|Consignment Agents where CONCOR is not having surh arrangements to provide gainful employment to need individuals and more revenue to CONCOR;

(b) what are the names of places/cities where CONCOR depots are functioning;

(c) what are the names of places|cties which are unrepresented;

(d) what are the names of dry port sites in the country where CONCOR is having direct cargo link; and

(e) what are the details of authorities empowered for appointment of such con-Sighment/Booking Agents alongwith the terms of their appointment, commission, facilities and incentives offered to needy persons so as to eradicate unemployment?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) Neither any Booking|Consignment agent has been appointed by CONCOR nor does it propose to appoint such agents.

(b) to (d) CONCOR is operating its depots at Bangalore, Anaparti, Guntur Coimbatore, New Delhi, Amingaon, Dhandari Kolan, Sanathnagar, Ahmedabad, Pune, Panipat, Moradabod, Tondiaepet, Wadi Bundar, Shalimar, Mulund and Vijayawada, All these depots are linked to one geteway port or more.

(e) Does not arise.

रेलवे बोर्ड

1103. डा० रत्नाकर पाण्डेय :
श्री अरंगिल श्रीधरन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार रेलवे बोर्ड के सदस्यों की संख्या 7 से घटाकर 6 करने पर विचार कर रही है ताकि खर्चे में कटौती की जा सके; यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : सरकार ने मितव्ययिता के उपाय के रूप में 31-3-1992 (अपराह्न) से रेलवे बोर्ड के एक सदस्य का पद (वेतनमान 8000 रुपये निर्धारित) कम करने का विनिश्चय किया है ।

Utilisation of railway land for Commercial purposes

1104. SHRI S. MADHAVAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government are considering a proposal to use the vacant land available with the Railway Board for commercial purposes and if so, what are the details;

(b) whether a pilot project in Bandra, Bombay to construct a multistorey building has been taken up by Indian Railway construction company and if so, what are the details thereof; and

(c) what is the total vacant land available with the Railway Board which can be utilised for commercial purposes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) The proposal is for exploring the feasibility of commercially exploiting space over railway land and land presently lying vacant or encroached upon, without obstructing the

use of the land by Railways when required, with a view to generating additional resources for Railways' developmental projects.

(b) No, Sir. There is, however, a proposal in this regard which is in initial stages.

(c) About 61,000 hectare of railway land is lying vacant at present, of which only a small portion will be suitable for commercial exploitation. The matter is in conceptual stage.

बगहा और छितौनी के बीच छोटी लाइन का बदला जाना

1105. **श्री राम नरेश यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बगहा और छितौनी के बीच छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य कब आरंभ हुआ था और इसकी अनुमानित लागत कितनी है ;

(ख) इस परियोजना का कार्य कब तक पुरा हो जाने की संभावना है और अभी तक इस पर कितनी राशि खर्च हुई है और इसके पूरा होने पर इस पर कितनी लागत आने की संभावना है ; और

(ग) इस परियोजना के कार्य के पूरा होने में बिलंब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) बगहा और छितौनी के बीच छोटी लाइन को बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने का कोई कार्य नहीं चल रहा है । बगहा और छितौनी के बीच लाइन पुनःस्थापन की एक परियोजना है ।

(ख) और (ग) 31-12-91 तक खर्च की गई राशि 30 करोड़ रुपये है, रेलवे, जल संसाधन मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश और बिहार की राज्य सरकारों के बीच लागत वहन की भागीदारी के आधार पर यह कार्य अनुमोदित किया गया है । यद्यपि रेलवे ने अपने पूरे हिस्से की राशि जमा करा दी है और जल-संसाधन मंत्रालय तथा बिहार सरकार अपने हिस्से की राशि जमा कराने के लिए सहमत है, परन्तु उत्तर प्रदेश सरकार अपने हिस्से की राशि जमा नहीं कर रही है । इस कार्य की प्रगति तथा इसका पूरा होना सभी सहभागीदारों द्वारा अपने हिस्से की राशि जमा करा देने पर निर्भर करेगा ।

शाहगंज से मऊ तक बाया आजमगढ़ मीटरगेज लाइन को बदलने की लागत

1106. **श्री राम नरेश यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहगंज जंकशन से मऊ जंकशन तक मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने में अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ;

(ख) इस लाइन पर कार्य कब तक आरंभ हो जाने की संभावना है ;

(ग) क्या इस परियोजना का कार्य वर्ष 1994 तक पूरा हो जाने की संभावना है ;

(घ) गत पांच वर्ष के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में रेलवे लाइनों पर अब तक जिलावार कितनी धन राशि खर्च की गई हैं ; और

(ङ) लाइन बदलने के संबंध में वर्तमान योजना का जिलावार ब्यौरा क्या है और उन पर कितने करोड़ रुपये की धन राशि खर्च किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इस परियोजना की अनुमानित लागत 40.59 करोड़ रुपये (1991-92 की दरों पर) है ।